associated with one designated party, and that too at a time when the Government is talking about financial austerity measures in the administration. I would like the Government to look into this matter.

Children falling sick due to inferior quality of mid-day Meals

श्री राजनीति प्रसाद (बिहार): सर, मुझे बहुत दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि "मिड-डे मील" बहुत ही अच्छे उद्देश्य से इस देश में लागू किया गया है, ताकि इससे बच्चे स्कूल जाएंगे और उनको दोपहर का भोजन मिलेगा। यह बहुत अच्छी बात है और सरकार ने भी "सर्व शिक्षा अभियान" के तहत इसको बढ़ाने का काम किया है। लेकिन यह "मिड-डे मील" ऐसा हो गया है कि आए दिन हमेशा अखबार में छपते हैं कि फलां स्कूल के बच्चे "मिड-डे मील" खाने के बाद बीमार पड़ गए। आज ऐसी घटनाएं बहुत सारे स्कूलों में हो रही हैं और इसके कारण कहीं-कहीं तो "मिड-डे मील" बंद कर दिया गया है या देते ही नहीं हैं।

सर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि इतने अच्छे काम के लिए क्या कोई administration नहीं है, क्या कोई infrastructure नहीं है कि इसको ठीक ढंग से चला सके? मैं यह आपसे जानना चाहूंगा और सरकार से जानना चाहूंगा कि वह इसके बारे में क्या करना चाहती है? मेरा यह कहना है कि "मिड-डे मील" के लिए सरकार से जो अनाज आता है और जो अनाज स्कूल में जाता है, जो समान स्कूल में जाता है, उसमें diversion होता है। स्कूल में खराब माल जाता है, घटिया माल जाता है और जो अच्छा माल सरकार से मिलता है, जो FCI के गोदाम से मिलता है, वह माल divert होकर बाजार में चला जाता है। बिहार में भी यही स्थिति है। इसका मतलब यह हुआ कि "मिड-डे मील" एक white elephant है और जो लोग स्कूल में इस काम का संचालन करते हैं, उनके संचालन में बहुत गड़बड़ी है, इसलिए मैं सरकार से यह मांग करुंगा कि "मिड-डे मील" के बारे में जरूर कुछ विचार करे। अगर आप विचार नहीं करेंगे, तो इतना pious जो आपका अभियान है, वह बिल्कुल फेल हो जाएगा और बच्चे डर से स्कूल नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर वे स्कूल जाएंगे, तो उनको "मिड-डे मील" दिया जाएगा और उसको खाने के बाद वे बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इसके बारे में जरूर कोई विचार करे।

श्री प्रशांत चटर्जी (पश्चिमी बंगाल): महोदय, मैं इस विषय से अपने को संबद्ध करता हूँ।

Withholding of additional Central Assistance by the Central Government to Uttarakhand

श्री भगत सिंह कोश्यारी (उत्तराखंड): माननीय उपसभापति महोदय, जनवरी, 2010 में हरिद्वार में महाकुंभ होने वाला है। इस कुंभ मेले के लिए केन्द्र सरकार प्रति वर्ष सहायता देती है। जब भी कुंभ मेला होता है, उसके लिए राशन में भी, जो चावल, गेहूं है, सरकार विशेष सहायता देती है। इस बार बड़ा दुर्भाग्य है कि "कुंभ मेला", जो देश का एक राष्ट्रीय event है, जिसमें देश भर से और विदेशों से भी लोग आते हैं, उसके लिए हमारी प्रदेश सरकार ने योजना आयोग के पास 400 करोड़ का स्पैशल पैकेज मांगा। इसके साथ-साथ प्रति वर्ष जो Additional Central Assistance (ACA) मिलती है और हर साल दस परसेंट बढ़कर मिलती है, उसके लिए 330 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान रखा, उसमें पैसा मांगा गया और 31.08.2009 को हमारे वित्त मंत्री जी की मुख्य मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष के साथ जो बैठक हुई, उसमें 730 करोड़ रुपए की बात तय हुई, लेकिन केंद्र सरकार ने उसमें जो 330 करोड़ रुपया है, ...(**व्यवधान**)...

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN (Kerala): Sir, where is the Minister?

श्री भगत सिंह कोश्यारी: जो हर साल ACA में मिलता है, वह ACA का पैसा काट देने से ...(**व्यवधान**)...

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: What is this, Sir? ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. ...*(Interruptions)*... Where are the Ministers?

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: Why is Zero Hour going on here? Who is going to respond? ...*(Interruptions)*... Sir, please adjourn the House. ...*(Interruptions)*...

SHRI PRASANTA CHATTERJEE (West Bengal): Sir, please adjourn the House. ...*(Interruptions)*... Let the Minister come. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu): During Zero Hour, no Minister has to respond. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. I cannot run the House without the Ministers. ...*(Interruptions)*... I cannot run the House without the Ministers. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI BRINDA KARAT (West Bengal): Sir, this is a contempt of the House. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned for five minutes.

The House then adjourned at seventeen minutes past twelve of the clock.

The House re-assembled at twenty-two minutes past twelve of the clock.

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.]

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Sir, they created unnecessary ... ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let the Minister give the explanation. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: The Minister was in the House. They don't want to run the House. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; no; please. ...*(Interruptions)*... No; No; ...*(Interruptions)*... One minute; let us not waste our time. ...*(Interruptions)*... आप बैठ जाइए प्लीज़।

THE MINISTER OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS (SHRI VAYALAR RAVI): Sir, I was sitting in the House and just for two minutes, I went to discuss some important matter with Mr. Arun Shourie. I was sitting. But, in the pandemonium, I could not hear what was going on. That has happened. That is why the whole thing happened. ...*(Interruptions)*... I came to know what happened after the House was adjourned.

Mr. Deputy Chairman, Sir, I regret the inconvenience caused to you and the House. ...*(Interruptions)*...

PROF. P.J. KURIEN (Kerala): Sir, kindly see ... ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, please. She can walk anywhere but not ... ...*(Interruptions)*...

SHRI ARUN SHOURIE (Uttar Pradesh): Sir, Mr. Ravi had come to discuss about the Business of the House. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: श्री भगत सिंह कोश्यारी। कोश्यारी जी, जहां तक आप बोल चुके थे, वहीं से आप शुरू कर दीजिए।

श्री भगत सिंह कोश्यारी: माननीय उपसभापति जी, माननीय मंत्री इधर तो बोलते हैं कि सब आए, लेकिन हमारे उत्तराखंड के बजट में 330 करोड़ रुपया ACA के अंदर, Additional Central Assistance के अंदर मिलना चाहिए था, जो हर साल मिलता है, हर साल दस परसेंट बढ़कर मिलता है। योजना आयोग के साथ जब हमारे माननीय मुख्य मंत्री और योजना मंत्री की बैठक हुई, उसमें यह तय था कि 400 करोड़ रुपया कुम्भ के लिए इस साल के लिए, one-time ACA के रूप में मिलेगा और उसके अलावा 330 करोड़ रुपया extra, जो हर साल दस परसेंट बढ़ाकर मिलता है, वह मिलेगा। उसकी स्वीकृति हो गयी लेकिन उसके बाद दुर्भाग्य से हमारे यहां योजना आयोग से जो रिपोर्ट आयी, उसमें इसका पूरा जिक्र नहीं आया और केवल one-time ACA के रूप में 400 करोड़ रुपया दे दिया। इस तरह से 330 करोड़ का नुकसान होने से जो हमारी बिजली की, पानी की, सड़क की या एजुकेशन की योजनाएं थीं, वे योजनाएं ठप्प होने के कगार पर हैं। इस प्रकार से या तो हम सारा रुपया कुम्भ में लगा दें या फिर उन योजनाओं को चलाएं। इस प्रकार से कुम्भ भी उससे प्रभावित हो रहा है और हमारी अन्य योजनाएं भी प्रभावित हो रही हैं। महोदय, हम पिछले तीन महीने से सरकार से कह रहे हैं कि सरकार को हमारे मेले के लिए जो राशन है – कम से कम 6000 मीट्रिक टन गेहूं, इतना ही चावल और इसी प्रकार से चीनी...(**व्यवधान**)...

PROF. P.J. KURIEN: Sir, if going to that side is objectionable, going to this side is also objectionable. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, please.

श्री भगत सिंह कोश्यारी: जो हमारा राशन है, इसको...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I think, it is better if some Ministers sit on the front Benches and not on the back Benches.

श्री भगत सिंह कोश्यारी: महोदय, अगर हमारी बात को नहीं सुना जाएगा तो कैसे काम चलेगा? यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, वहां पर लोगों में असंतोष फैला हुआ है। महोदय, 2001 के कुम्भ के मेले में, चाहे प्रयाग का हो या 1998 का हरिद्वार का मेला हो, एपीएल के अंदर राशन राज्य सरकारों को दिया गया, लेकिन आज हमारे यहां की केन्द्र सरकार एपीएल का जो राशन है, वह देने के स्थान पर यह कहती है कि तुम खुले बाज़ार से गेहूं और चावल लो। महोदय, आप जानते हैं कि उत्तराखंड एक पिछड़ा हुआ इलाका है। अगर वहां पर तुरंत सरकार ने एपीएल में राशन नहीं दिया तो हमारे लिए कुम्भ को चलाना मुश्किल हो जाएगा। अगर उन्होंने इसी प्रकार से 303 करोड़ रुपया कट कर दिया तथा नहीं दिया, तो आप जानते हैं कि हमारा स्टेट बॉर्डर का इलाका है, इधर से चायना और उधर से नेपाल है, मैं सोचता हूं कि इससे हमारी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। इस कारण हमारे साथ भेदभाव करना और कुम्भ को खतरे में डालना, सही नहीं है। महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार तत्काल पुनर्विचार करके वह राशि हमको दे और आवश्यक राशन भी हमको दे। धन्यवाद।

DR. (SHRIMATI) NAJMA A. HEPTULLA (Rajasthan): Sir, we associate ourselves with the matter raised by the hon. Member.

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा): महोदय, मैं भी इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

Non payment of promised assistance to victims of 26/11 terrorist attacks in Mumbai

श्री प्रकाश जावडेकर (महाराष्ट्र): उपसभापति महोदय, आज 26/11 है, एक साल हुआ है मुम्बई पर हुए हमले को। इसमें 164 लोग मरे थे और 239 लोग जख्मी हुए थे। लेकिन एक साल के बाद हमने तो श्रद्धांजलि दे दी, जो लोग वीरगति को प्राप्त हुए तथा हताहत हुए थे। लेकिन इस बारे में क्या केवल श्रद्धांजलि से ही काम चलेगा? सरकार ने इन लोगों के लिए जो पैकेज घोषित किया था, क्या एक साल के बाद वह उनको मिला है?